केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :45 अंक 198 गुरूवार 8 फरवरी 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

बस्ती में धारा 144 लागू

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिला मजिस्ट्रेट अंद्रा वामसी ने पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2024 तक धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। इस संबंध में उन्होने बताया कि विभिन्न त्यौहार एवं परीक्षाए होनी है, यथा 11 फरवरी को सहायक समीक्षा अधिकारी/समीक्षा अधिकारी (प्रा.) परीक्षा 2023, 22 फरवरी से 9 मार्च तक हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की संयुक्त परीक्षा वर्ष 2024, 14 फरवरी को बंसत पंचमी, 24 फरवरी को संत रविदास जयंती, 26 फरवरी को शबे बरात, 08 मार्च को महाशिवरात्रि तथा 24 व 25 मार्च को होली का त्यौहार है।

उन्होने बताया कि इसके अलावा कोविड–19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करने के साथ ही जनपद में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को नकलविहीन, सकुशल एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था चुस्त–दुरूस्त रखने के लिए ये आदेश लागू किए गये है। इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा–51 से 60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

पुलिस चौकी के निकट अज्ञात बुर्जुग का शव बरामद

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

विक्रमजोत (बस्ती)। छावनी थानाक्षेत्र के विक्रमजोत चौकी के समीप बुधवार की सुबह हाईवे के बगल में एक अज्ञात साधू वेश धारी बुजुर्ग की शव मिला। जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम हेतु भेजा दिया है।

जानकारी के अनुसार विक्रमजोत कस्बे के बासु बंगाली मिष्ठान भंडार पर मंगलवार की शाम करीब 9 बजे एक साधु बीमारी की अवस्था में आए। बीमारी हालत को देखकर दुकान संचालक विश्वजीत विश्वास(बासु बंगाली मिष्ठान भंडार) के द्वारा समीप के निजी चिकित्सक से साधु का दवा इलाज करवा कर कंबल इत्यादि उपलब्ध कराकर सड़क किनारे एक बंद दुकान में सोने की व्यवस्था करा दी गई।

स्थानीय लोगों कि माने तो सुबह 6 बजे सोकर उठे साधु ने भजन कीर्तन किया लगभग दो घंटे पश्चात करीब 8 बजे अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। चौकी इंचार्ज चंद्रकांत पाण्डेय ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि सुबह बातचीत के दौरान कुछ लोगों से उन्होंने अपना नाम सच्चिदानंद अयोध्या राम हाल्ट बताया था।

अयोध्या बस्ती में आसपास के थानो मे लोगों से साधु महाराज के शव को दिखाया गया इनके बारे में पूछा गया तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा इनकी पहचान नहीं की गई है शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, शव को मर्चरी हाउस भेजा जा रहा है। तथा पहचान कराई जाने का प्रयास किया जा रहा है।

किसान सोलर पम्प के लिये करें ऑन लाइन आवेदन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । वर्ष 2023–24 में पी. एम. कुसुम योजनान्तर्गत सोलर पम्प हेतु पहले आओ–पहले पाओं के आधार पर आनलाइन बुकिंग करा सकते है। उक्त जानकारी देते हुए संयुक्त निदेशक कृषि अविनाश चंद्र तिवारी ने बताया है कि आवेदन विभागीय पोर्टल upagriculture.up.gov.in पर आगामी 12 फरवरी तक ही लिये जायेंगे। इच्छुक कृषक भाई जनपद में सोलर पम्पों के लक्ष्यों की सीमा तक उक्त तिथि तक आवेदन कर सकते है। विस्तृत जानकारी के लिए अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

मुख्यमंत्री योगी बोले हम सिर्फ कहते नहीं करके दिखाते हैं

लखनऊ (आभा)। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। पांच फरवरी को बजट पेश करने के बाद राम मंदिर जाने को लेकर भाजपा और सपा में बयानबाजी जारी है। भाजपा ने सभी विधायकों को 11 फरवरी को अयोध्या दर्शन कराने का आमंत्रण दिया जिसे सपा नेताओं ने अस्वीकार कर दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यूपी के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। वो कहीं जाते थे तो रहने के लिए उन्हें कमरा नहीं मिलता था पर

अब ये पहचान का संकट खत्म हो गया है।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की छवि में बदलाव किया है। प्रदेश तरक्की कर रहा है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। देश ही नहीं दुनिया के नक्शे पर यूपी को पहचान मिल रही है। अयोध्या में विदेशों से पर्यटक आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पांडवों ने कौरवों से सिर्फ पांच गांवों की मांग की थी पर वो नहीं दिया गया। देश का बहुसंख्यक समाज तो सिर्फ तीन स्थानों (अयोध्या, मथुरा और काशी) की मांग कर रहा था उसके लिए उसे गिड़गिड़ाना पड़ा।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। इसके जरिये भारत के गौरव की पुर्नप्रतिष्ठा हुई है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि अयोध्या का पुराना गौरव वापस लौट आया है। हमें खुशी है कि हमने अपना वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया...। मुख्यमंत्री योगी बोले कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि करके दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अयोध्या के साथ अन्याय हुआ। वहां के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मंदिर का मामला तो न्यायालय में था तो क्या वहां सड़क और बिजली नहीं दी जा सकती थी। क्या सरयू के घाटों की सफाई नहीं की जा सकती थी लेकिन अयोध्या को कृत्सित मंशा के कारण अभिशप्त रखा गया।

भूमि संरक्षण अधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । भूमि संरक्षण विभाग (जल संसाधन) द्वारा पिछले तीन माह से गूल निर्माण में कोई भौतिक या वित्तीय प्रगति ना पाए जाने पर जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने भूमि संरक्षण अधिकारी का वेतन रोकते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई के लिए डीओ लेटर भेजने का निर्देश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जल संचयन संबंधी बैठक में उन्होंने पाया कि भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शून्य है। कुल रुपया 4 करोड़ के सापेक्ष मात्र 86 लाख रुपया ही व्यय हो पाया है। इस संबंध में भूमि संरक्षण अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

नगर पालिका परिषद बस्ती में रूफटॉप हार्वेस्टिंग के संबंध में पाई गई अनियमितता को 10 दिन के भीतर सुधार करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा ईओ नगरपालिका को निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी द्वारा इस कार्य की अधिकारियों की टीम द्वारा जांच कराई गई थी, जिसमें निर्माण कार्य अपूर्ण पाया गया था तथा टूटफूट पाई गई थी। इस कार्य को सही करने के लिए नगर पालिका को निर्देशित किया गया है। नवनिर्मित 30 नलकूपों में से बीस नलकूपों में धनराशि जमा करने के बावजूद विद्युत विभाग द्वारा ऊर्जीकरण न किए जाने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया है तथा इस संबंध में सीडीओ को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया है।

जिलाधिकारी ने जल निगम विभाग द्वारा वर्ष 2018 की एमएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत 5 परियोजनाओं को अब तक पूरा न किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है तथा इस संबंध में शासन को डीओ लेटर भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने बैठक में सिंचाई, बाढ़, लघु सिंचाई, भूगर्भ जल, नगर पालिका एवं नगर पंचायत की जल संसाधन संबंधी योजनाओं की समीक्षा किया तथा समय से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है।

बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, अधिशासी अभियंता जल निगम जनार्दन सिंह, बाढ़ के दिनेश कुमार, सरयू नहर खंड 4 के राकेश कुमार गौतम, नलकूप के संतलाल, ईओ नगर पालिका सत्येंद्र सिंह, कृषि अधिकारी डॉ. राज मंगल चौधरी तथा विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।

छावनी फ्लाइओवर निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर लगाई फटकार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिलाधिकारी अंद्रा वामसी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुयी। समीक्षा में उन्होने पाया कि छावनी फ्लाइओवर निर्माण कार्य की प्रगति धीमी पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त किया। उन्होने संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने का निर्देश एडीएम को दिया है।

समीक्षा में उन्होने पाया कि 71 लाइसेंस निलम्बित किया गया है। उन्होने राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर मरम्मत तथा साइनेज लगाने का कार्य समय से पूरा करने, कप्तानगंज, मनौरी व पटेल चौराहे पर रम्बल स्ट्रिप लगाने तथा छावनी फ्लाइओवर पर दोनों तरफ सुरक्षात्मक उपाय ससमय पूर्ण करने पर एनएचआई की सराहना किया।

जनपद की सीमान्तर्गत मार्गवार दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि पुलिस विभाग व राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी संयुक्त निरीक्षण करते हुए चिन्हित स्थानों पर आवश्यक कार्यवाही किया जाय। उन्होने पाया कि दिसम्बर माह में 3 से अधिक मृत्यु वाली कोई घटना नही हुयी है। ट्रैफिक कामिंग मेजर्स की समीक्षा में पाया कि एनएचआई के अधीन दो मार्ग की लम्बाई 126.5 किमी. की है, जिसमें 22 जंग्शन चिन्हित किये गये है। इसी प्रकार राष्ट्रीय मार्ग खण्ड के अधीन कुल 2 की कुल लम्बाई 61.55 किमी. है, जिसमें एनएच 227ए रामजानकी मार्ग पर माइनर जंग्शन 11 है, जिनके ट्रैफिक कामिंग का कार्य पूर्ण है।

बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, एडीएम कमलेश चन्द्र, एसडीएम सदर गुलाब चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी केशवलाल एवं अवधेश कुमार, ईओ नगरपालिका सत्येन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी पुलिस विनय कुमार चौहान, डीएसटीओ ईशा शर्मा, एआरटीओ पंकज कुमार तथा एनएचआई के अधिकारीगण उपस्थित रहें।

उत्तराखंड में ध्वनिमत से पास हुआ समान नागरिक संहिता बिल

देहरादून (आभा)। उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया। विधानसभा में चर्चा के बाद आज समान नागरिक संहिता का बिल पास हो गया। दिनभर विधानसभा में बिल को लेकर चर्चा हुई वहीं, इसके बाद सीएम का संबोधन हुआ। बुधवार शाम को यूसीसी बिल ध्वनिमत से पास कर दिया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इस बिल को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। साथ ही आंदोलनकारियों के आरक्षण का बिल भी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।

इसके बाद सीएम धामी ने प्रेसवार्ता में कहा कि आज उत्तराखंड के लिए विशेष दिन है। मैं विधानसभा के सभी सदस्यों, जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उनके समर्थन से ही हम आज ये कानून बना पाए हैं। मैं पीएम मोदी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। ये कानून समानता का है। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए, बल्कि उन माताओं बहनों का आत्मबल बढ़ाएगा, जो किसी प्रथा, कुरीति की वजह से प्रताड़ित होती थीं। हमने 12 फरवरी 2022 को इसका संकल्प लिया था। इसे

जनता के सामने रखा था।

सीएम धामी ने कहा कि करीब दो साल में आज सात फरवरी को हमने इसे सदन से पास करवाया। देश के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि वह इस दिशा में आगे बढ़ें। उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव के समय हमारी पार्टी ने संकल्प लिया था, इसे आगामी चुनाव के नजरिये से न देखा जाए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का बड़ा योगदान है। आंदोलनकारियों की सुविधा, पेंशन बढ़ाने से लेकर हमने आरक्षण देने का काम किया है।

विधेयक में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों को ही शामिल किया गया है। इन विषयों, खासतौर पर विवाह प्रक्रिया को लेकर जो प्राविधान बनाए गए हैं उनमें जाति, धर्म अथवा पंथ की परंपराओं और रीति रिवाजों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वैवाहिक प्रक्रिया में धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़े गा। धार्मिक रीति–रिवाज जस के तस रहेंगे। –

अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत का वेतन रोका

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माण कार्यो की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया है कि निर्माण कार्यो में तेजी लायी जाय। साथ ही साथ निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि को समय से रिलीज किया जाय। उन्होने विभागीय कार्यो में शिथिलता पाये जाने पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अधिकारी का वेतन बाधित किया है। समीक्षा में उन्होने पाया कि लोक निर्माण विभाग के तहत स्वीकृत 25 सड़को में से 18 पूर्ण हो गयी है। उन्होने गैस पाइपलाईन का कार्य 15 फरवरी तक पूर्ण कराये जाने का निर्देश संबंधित कार्यदायी संस्था को दिया है।

बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, उप जिलाधिकारी गुलाब चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी केशवलाल व अवधेश कुमार, डीएसटीओ ईशा शर्मा, ईओ नगरपालिका सत्येन्द्र सिंह, बीएसए अनूप तिवारी तथा कार्यदायी संस्था के अधिकारीगण उपस्थित रहें।

विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने सदन में उठाया वाल्टरगंज चीनी मिल पर गन्ना किसानों, श्रमिकों के बकाया भुगतान का मुद्दा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने बजट सत्र के दौरान शिक्षा मित्रों को स्थायी शिक्षक बनाने, ओ. बी.सी. को नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ दिये जाने, महापुरूषो के मूर्तियों की सुरक्षा करने, मूर्तियां खण्डित करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई, बस्ती के बंद पड़ी चीनी मिल पर गन्ना किसानों के 45 करोड़ रूपये बकाये का भुगतान कराकर श्रमिकों का वेतन भुगतान कराने, बस्ती जिला अस्पताल एवं मेडिकल कालेज में हृदय रोग, न्यूरो चिकित्सकों के तैनाती किये जाने, कांदू, कसौधन, साहू समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, मेडिकल कालेज मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने के साथ ही मुण्डेरवा क्षेत्र के अनेक सड़कों के निर्माण का मुद्दा उठाया।

सदर विधायक एवं समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष महेन्द्रनाथ यादव ने जनपद की समस्याओं को प्रमुखता से विधानसभा में उठाते हुये अधूरे पड़े इंजीनियरिंग कालेज को शुरू कराये जाने की मांग किया। कहा कि वाल्टरगंज की चीनी मिल भाजपा की सरकार में बंद हुई और यहां गन्ना किसानों का 45 करोड़ रूपये का भुगतान बाकी

–बस्ती में हृदयरोग, न्यूरो चिकित्सकों की तैनाती, शिक्षा मित्रों को स्थायी शिक्षक बनाने की मांग

है, किसान परेशान हैं, मिल के मजदूर भुखमरी के शिकार है। इनका भुगतान तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराया जाय। महापुरूषों की प्रतिमाओं को आये दिन खण्डित किये जाने का मुद्दा उठाते हुये उन्होने मांग किया कि उनकी सुरक्षा के साथ ही दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय। सदर विधायक ने सदन में जनपद से जुड़ी अनेक समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुये उनके समाधान की मांग किया। विधायक महेन्द्रनाथ ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुये सदन का ध्यानाकर्षण किया कि उन्हें स्थायी शिक्षक बनाया जाय।

सदर विधायक ने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से जल शक्ति मंत्री से पूंछा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने में खुदाई के दौरान कितनी सड़के क्षतिग्रस्त हुई है। क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत के लिये सरकार के पास क्या योजना है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने इसके उत्तर में बताया कि जलजीवन मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाने में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं उन्हें पुर्न स्थापित करने का दायित्व कार्यदायी एजेन्सी के अनुबंध में है।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा 9 को करेंगे बस्ती के विकास कार्यों का निरीक्षण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा आगामी 09 फरवरी को कप्तानगंज विकास खण्ड के बढनी मिश्र गॉव के प्रस्तावित भ्रमण के मद्देनजर जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने विभागीय अधिकारियों को तैयारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होने निर्देश दिया है कि लाभार्थीपरक योजनाओं में चयनित लाभार्थियों को मुख्य सचिव द्वारा सामग्री का वितरण कराया जायेंगा। उनके द्वारा गॉव का निरीक्षण किया जायेंगा, इसलिए वृहद साफ–सफाई के निर्देश दिये है। स्कूल, आगनबाड़ी, तालाब की सजावट, पर्यटन कार्य, पौध रोपण का कार्य, मिट्टी की सड़क को ठीक कराने का कार्य ससमय पूर्ण कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।

उन्होने कहा कि राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा गॉव में रू0 1.

40 करोड की लागत से विकास कार्य कराये जा रहे है। मुख्य सचिव द्वारा इसका निरीक्षण किया जायेंगा। इस दौरान उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास, पी.एम. किसान सम्मान निधि, विश्वकर्मा टूलकिट, स्पोर्ट्स किट, गोल्डन कार्ड, ऋण वितरण, कृषि यंत्र, जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत टैप कनेक्शन के चिन्हित लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेंगा। उन्होने यह भी निर्देश दिया है कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा यथा–विकसित भारत संकल्प यात्रा से संबंधित एलईडी वैन, स्वास्थ्य कैम्प, स्वीप जागरूकता, कृषि, आईसीडीएस, श्रीअन्न, एनआरएलएम के स्टाल लगाये जायेंगें।

उन्होने डीएफओ को निर्देशित किया है कि वहॉ वृक्षारोपण की व्यवस्था कराये। सीएमओ स्वास्थ्य कैम्प आयोजन के साथ–साथ नेशनल क्वालिटी एंश्योरेंस स्टैण्डर्ड के तहत सम्मानित भानपुर की स्वास्थ्य, आईसीडीएस, ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित कराने की व्यवस्था करायेंगे। साथ ही गोल्डन कार्ड वितरण के लिए लाभार्थी का चयन करेंगे। अपर पुलिस अधीक्षक कार्यक्रम में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। मुख्य सचिव द्वारा गॉव में स्थित प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, एएनएम सेण्टर, मत्स्य तालाब, हेल्थ वेलनेस सेण्टर, आगनबाड़ी केन्द्र एवं पंचायत भवन का निरीक्षण भी किया जा सकता है।

बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, सीएमओ डा. रमाशंकर दुबे, अपर जिलाधिकारी कमलेश चन्द्र, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, डीडीओ संजय शर्मा, पीडी राजेश झा, अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, उप जिलाधिकारी गुलाब चन्द्र, विनोद पाण्डेय, कृषि अधिकारी डा. राजमंगल चौधरी, डीपीआरओ रतन कुमार, पर्यटन अधिकारी विकास नारायण, बीएसए अनूप तिवारी, अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी केशवलाल एवं अवधेश कुमार, विद्युत के मनोज सिंह तथा ज्ञान प्रकाश, कार्यक्रम अधिकारी रेखा गुप्ता, कीडाधिकारी सहित विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहें।

श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण सम्पन्न

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बस्ती शाखा के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह प्रेस क्लब सभागार में सम्पन्न हुआ। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सांकृत्यायन के संरक्षक डॉ. रामकृष्ण लाल 'जगमग' जिलाध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा, राजेश कुमार पाण्डेय महामंत्री, राकेश त्रिपाठी कोषाध्यक्ष, धर्मेन्द्र पाण्डेय, अरूण कुमार को उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार श्रीवास्तव, राकेश गिरी को सचिव पद हेतु गोपनीयता की शपथ दिलायी। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी सदस्य दीपक द्विवेदी, देवेन्द्र पाण्डेय, जय प्रकाश उपाध्याय, श्रीप्रकाश श्रीवास्तव को शपथ दिलाया गया।

वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सांकृत्यायन ने कहा कि पत्रकारिता

–पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिये होगी पहल– डा. वी.के. वर्मा

के अपने दायित्व हैं, पत्रकारों को इस भूमिका पर खरा उतरना होगा। प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने कहा कि पत्रकारिता के लिये शब्द साधना आवश्यक है। पत्रकार प्रदीप चन्द्र पाण्डेय ने पत्रकारों का आवाहन किया कि वे इस क्षेत्र की पवित्रता और विश्वास को बचाये बनाये रखने में योगदान दें। संरक्षक डॉ. रामकृष्ण लाल 'जगमग' ने कहा कि ज्ञान पत्रकारिता की आवश्यक शर्त है। निरन्तर अध्ययन आवश्यक है।

उपस्थित पत्रकारों और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुये जिलाध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि पत्रकारों की समस्याओं का प्रमुखता से समाधान कराया जाय।

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य रूप से अशोक श्रीवास्तव, लवकुश सिंह, राकेश तिवारी, राजेन्द्र उपाध्याय, विन मौर्य, राम विलास कसौधन, फैय्याज, अनिल कुमार श्रीवास्तव, श्री प्रकाश गुप्ता, मो. कलीम, मो. रिजवान, सुमित जायसवाल, दिलीप चन्द्र पाण्डेय, कपीश मिश्र, लवकुश यादव, अनूप मिश्र, धर्मेन्द्र यादव, आशुतोष नारायण मिश्र, बजरंग प्रसाद शुक्ल, शिवेश शुक्ल, जितेन्द्र कुमार, जगदम्बा प्रसाद 'भावुक' के साथ ही अनेक पत्रकार एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षकों की बैठक में बनी महाहड़ताल की रणनीति

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को बीआरसी सल्टौआ सभागार में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक सम्पन्न हुई। संघ के जिला संयुक्त मंत्री विजय प्रकाश चौधरी व ब्लाक अध्यक्ष राम भरत वर्मा ने शिक्षक–शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी बजट 2024 में शिक्षक–कर्मचारियों की घोर उपेक्षा की गई । बजट में पुरानी पेंशन बहाली व कैशलेस चिकित्सा के बारे मे कुछ नहीं किया गया जिससे शिक्षक– कर्मचारियों में घोर निराशा व्याप्त है। शिक्षक कर्मचारी आंदोलित हैं । कहा कि पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच 'एनएसजीए'

–केन्द्र और यूपी के बजट में शिक्षकों की घोर उपेक्षा–विजय प्रकाश

द्वारा घोषित होने वाले महा हड़ताल में शिक्षक – शिक्षिकाओं को विद्यालयों में पूर्ण तालाबंदी करते हुए हड़ताल में शामिल होना है और अपनी एकजुटता दिखानी हैं । ये सरकार झुकेगी और पुरानी पेंशन बहाल करेगी चुनावी वर्ष है और इस महाहड़ताल में आर पार की लड़ाई होगी ।

शिक्षक नेता विजय प्रकाश चौधरी ने कहा कि शिक्षक और राज्य कर्मचारियों के लिये यह करो या मरो का समय है। यदि इस बार चूके तो पेंशन बहाल नहीं हो पायेगी और बुढापे की लाठी टूट जायेगी। महाहड़ताल में पूरी ताकत से जुड़ना होगा जिससे पुरानी पेंशन बहाल हो। बैठक में जिला उपाध्यक्ष संदेश रंजन, ब्लॉक मंत्री बब्बन पाण्डेय,संयुक्त मंत्री चन्द्रशेखर पाण्डेय, उपाध्यक्ष रमेश चंद्र चौधरी,अजय त्रिपाठी,रमेश विश्वकर्मा,सौरभ पद्माकर, अनुराधा चौधरी, प्रियंका पटेल, ए0आर0 पी0 गिरिजेश सिंह, अविनाश दूबे,शिव कुमार,वीरेंद्र पाण्डेय सहित सैकड़ों शिक्षक व शिक्षा मित्र उपस्थित रहे ।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 8 फरवरी 2024 गुरूवार

सम्पादकीय

समान नागरिक संहिता

पर्वतीय राज्य उत्तराखंड ने एक इतिहास बनाया, जब वह देश का पहला राज्य बना, जिसने एक समान नागरिक संहिता लागू की। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद यह भाजपा का तीसरा मुख्य एजैंडा रहा है। उत्तराखंड में एक समान नागरिक संहिता सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों के बाद लागू की गई। एक समान नागरिक संहिता पर मूलतः लंबे समय से चर्चा चल रही है और यह एक बहुप्रतीक्षित कानूनी सुधार है, जिसका उद्देश्य विवाह पंजीकरण, बाल अधिरक्षा, तलाक, दत्तक ग्रहण, संपत्ति अधिकार, अंतर राज्य संपत्ति अधिकार जैसे पर्सनल कानूनों में धर्म को ध्यान में न रखते हुए एकरूपता लाना है। इसमें महिलाओं, बच्चों, विकलांगों के हितों की सुरक्षा करने और पैतृक संपत्ति के मामले में लड़कियों को समान अधिकार देने तथा लिंग समानता सुनिश्चित करने को भी महत्व दिया गया है।

उत्तराखंड में बहु विवाह प्रथा, बाल विवाह और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे कानून में धर्म को सामाजिक संबंधों और विवाह, उत्तराधिकार परिवार, भूमि आदि के मामले में पर्सनल कानून से अलग रखा गया है तथा हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू कोड बिल, शरिया लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 आदि धर्म के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों में सुधार के विवादास्पद मुद्दों का निराकरण किया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी भारतीयों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, लिंग समानता स्थापित की जाएगी, महिलाओं की दशा में सुधार में सहायता की जाएगी। हालांकि जन जातीय लोगों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता विद्यमान भेदभावपूर्ण प्रथाओं के कारण उत्पन्न हुई और यह सामाजिक सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिससे असमानताएं और विषमताएं समाप्त हों और मौलिक अधिकारों का पालन हो। भाजपा के अनुसार स्पष्ट है कि किसी भी देश में धर्म आधारित कानून नहीं होने चाहिएं और सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। इसके अलावा एक समान नागरिक संहिता में कमजोर वर्गों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा दी गई है तथा एकता के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया गया है।

स्वाभाविक रूप से विपक्ष ने इसका इस झूठे आधार पर विरोध किया है कि यह धार्मिक समूहों के व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप करेगा और उनका कहना है कि इसे तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए, जब तक धार्मिक समूह इस बदलाव के लिए तैयार न हों। यह अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का मुद्दा है और हिन्दुत्व ब्रिगेड की भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए नीति है। यह भारत को विखंडित करेगा और इसकी विविधतापूर्ण संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा। वर्ष 2014 के बाद से भारत की राजनीतिक वास्तविकता में बहुत बदलाव आया है और आधुनिक समाज धीरे–धीरे एकजुट बन रहा है, जहां पर धर्म, समुदाय और जाति की परंपरागत सीमाएं धीरे–धीरे समाप्त हो रही हैं तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर रही हैं और इस भावना को उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में व्यक्त किया है।

इस कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि यह अपनी पसंद के धर्म को मानने की संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, जिसमें विभिन्न धर्मों को अपने वैयक्तिक कानूनों को मानने की अनुमति दी गई है। उदाहरण के लिए, संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक धार्मिक समूह को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने का और अनुच्छेद 29 उनकी विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। संविधान सभा की मौलिक अधिकार उपसमिति ने एक समान नागरिक संहिता को जानबूझकर मौलिक अधिकार नहीं बनाया था।

एक समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क दिए जा रहे हैं और इसका निराकरण मध्यमार्गीय है, किंतु इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि एक समान नागरिक संहिता से भाजपा को चुनावी लाभ होगा। इसके अलावा राम मंदिर के निर्माण का उपयोग भी विपक्ष को हाशिए पर लाने के लिए किया जाएगा। भाजपा का कहना है कि विपक्ष मुस्लिम समर्थक है। अधिकतर हिन्दू इन निर्णयों को भाजपा को अपने मूल एजैंडा को लागू करने के रूप में देखेंगे।

तथापि कुछ लोग एक समान नागरिक संहिता को लेकर इस बात से चिंतित हैं कि इसके माध्यम से सभी समुदायों पर हिन्दू कृत्य कोड संहिता को लागू किया जाएगा और इसमें विवाह जैसे व्यक्तिगत मुद्दों के बारे में प्रावधान होंगे, जो हिन्दू परंपराओं के अनुरूप होंगे और इसके माध्यम से अन्य समुदायों को भी कानूनी रूप से उन्हें मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञ में इस बारे में मतभेद है कि क्या किसी राज्य के पास एक समान नागरिक संहिता लागू करने की शक्ति है। कुछ का मानना है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकार जैसे मुद्दे संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 52 में आते हैं और इस पर केन्द्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसलिए राज्य सरकारों को इस कानून को बनाने और लागू करने की शक्ति प्राप्त है।

तथापि कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि राज्यों को एक समान नागरिक संहिता बनाने का अधिकार देने से अन्य व्यावहारिक समस्याएं पैदा होंगी। जरा सोचिए यदि गुजरात में एक समान नागरिक संहिता हो और वहां पर दो लोग विवाह करते हैं और फिर वे राजस्थान जाते हैं तो उन पर कौन सा कानून लागू होगा? एक समान नागरिक संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और यह बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 47 में प्रावधान है कि राज्य मादक द्रव्यों और औषधियों के सेवन का प्रतिषेध करेगा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं, किंतु अधिकतर राज्यों में शराब की बिक्री हो रही है और अलग–अलग राज्यों में शराब पीने की अलग–अलग कानूनी आयु निर्धारित की गई है।

प्रश्न उठता है कि एक समान नागरिक संहिता में ऐसा क्या है कि हिन्दुत्व ब्रिगेड के नेताओं को छोड़कर अन्य सारे राजनेता इसका विरोध करते हैं? इसको अल्पसंख्यक विरोधी क्यों माना जाता है? यदि हिन्दू पर्सनल लॉ का आधुनिकीकरण और परंपरागत ईसाई प्रथाओं को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ को पवित्र क्यों माना जाना चाहिए? क्या राज्य धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करता है? गत वर्षों में धर्म की विकृत व्याख्याएं की गई हैं और इसका इस्तेमाल संकीर्ण व्यक्तिगत राजनीतिक एजैंडा और वोट बैंक के लिए किया गया है और इससे देश का वातावरण खराब हुआ है तथा इस महत्वपूर्ण तथ्य की उपेक्षा की गई है कि अंबेडकर ने वैकल्पिक एक समान नागरिक संहिता का पक्ष लिया था। उन्होंने दो टिप्पणियां की थीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार किया जा सकता है और यह सारे भारत में एक जैसा नहीं है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

क्या बिखर जायेगा सपा, रालोद का गठबंधन

–नीरज कुमार दुबे–

विपक्ष के इंडी गठबंधन की नाव डूबती देख इस पर सवार राजनीतिक दलों में कूद कर अपनी जान बचाने की होड़ देखने को मिल रही है। इंडी गठबंधन की नाव को जिन नीतीश कुमार ने तैयार किया था वही सबसे पहले यहां से दूसरी तरफ कूद गये जिससे नाव का संतुलन गड़बड़ा गया। मौका देख ममता बनर्जी ने भी इस नाव से दूरी बना ली और अब राष्ट्रीय लोक दल भी इससे कूदने के लिए पूरी तरह तैयार है। आम आदमी पार्टी भी इंडी गठबंधन की नाव से कूदने के लिए अपना सामान समेट रही है। इस गठबंधन में अब जो दल बचे हैं वह या तो आपस में ही लड़ रहे हैं या उन दलों के भीतर ही भितरघात देखने को मिल रही है जिसके चलते किसी का चुनाव चिह्न खतरे में पड़ गया है तो किसी की पार्टी का मालिकाना हक किसी और के पास चला गया है। विपक्ष की यह स्थिति देख अब प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिये गये संबोधन की वह बात किसी को अतिश्योक्ति नहीं लग रही कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनावों में अकेले दम पर 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 के पार जायेगा।

विपक्षी गठबंधन की हालत से देश के सामने एक बात और स्पष्ट हो गयी है कि बेमेल विचारधारा वाला यह गठबंधन सिर्फ सत्ता स्वार्थ के लिए बना था। जहां तक राष्ट्रीय लोक दल की बात है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका भाजपा के साथ आना तय हो चुका है। एकाध दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि राष्ट्रीय लोक दल का भाजपा में विलय भी संभव है लेकिन अगर विलय नहीं हुआ तो गठबंधन होना पक्का है। हम आपको याद दिला दें कि भाजपा ने राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन का प्रयास उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी किया था लेकिन तब जयंत चौधरी ने साथ आने से मना कर दिया था। राष्ट्रीय लोक दल 2014 से सभी चुनाव विपक्षी दलों के साथ मिलकर लड़ा है लेकिन इसका उसे कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। हालांकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में जरूर समाजवादी पार्टी से गठबंधन का रालोद को फायदा हुआ था साथ ही सपा कोटे से जयंत चौधरी को राज्यसभा की सदस्यता भी मिल गयी थी।

लेकिन अब छोटे चौधरी के नाम से मशहूर जयंत चौधरी के पाला बदलने की अटकलों से विपक्षी खेमा बेचौन दिख रहा है। क्योंकि बात यह नहीं है कि छोटा दल गठबंधन से बाहर जा रहा है या बड़ा दल, बात यह है कि लंबे समय से गठबंधन में साथ रहा दल अब दूसरे के साथ जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि हाल ही में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ एक फोटो ट्वीट करते हुए ऐलान किया था कि रालोद के लिए गठबंधन में सात लोकसभा सीटें दी गयी हैं। लेकिन यह सात सीटें कौन–सी होंगी इसका ऐलान नहीं किया गया था। इस बात से जयंत चौधरी नाराज बताये जा रहे थे। जयंत चौधरी ने राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान भी कांग्रेस से कुछ सीटें अपने लिये मांगी थीं लेकिन कांग्रेस की ओर से स्पष्ट इंकार कर दिये जाने के चलते उन्हें निराशा हाथ लगी थी। इसलिए जब भाजपा की ओर से इस बार गठबंधन का प्रस्ताव आया तो उसे जयंत चौधरी मना नहीं कर सके। बताया जा रहा है कि भाजपा के साथ जाने पर जयंत चौधरी को मथुरा, कैराना, अमरोहा और बागपत सीटें मिल सकती हैं। अभी इनमें से अमरोहा को छोड़कर बाकी तीनों सीटें भाजपा के पास हैं। बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी भाजपा के प्रस्ताव को स्वीकार करने का मन बना चुके हैं क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के क्षेत्रीय दल के दर्जे को बचाना है। यदि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार इन लोकसभा चुनावों में मत हासिल नहीं किये तो संभव है कि उनका चुनाव चिह्न नल भी छिन जाये। जयंत चौधरी यह बात समझ रहे हैं कि भले समाजवादी पार्टी उन्हें लड़ने के लिए ज्यादा सीटें दे दे लेकिन सीटें जीतने की ज्यादा संभावना भाजपा के साथ मिलकर लड़ने में ही है।

दूसरी ओर भाजपा भी यह समझ रही है कि किसान आंदोलन के दौरान से नाराज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मतदाताओं को पूरी तरह तभी साधा जा सकता है जब राष्ट्रीय लोकदल साथ आ जाये। हम आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चुनावी नुकसान पश्चिमी क्षेत्र में ही हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी भाजपा का प्रदर्शन इस क्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप नहीं था इसलिए भाजपा 2024 में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। भाजपा का प्रयास है कि इस बार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल की जाये और इसके लिए तमाम प्रयास किये भी जा रहे हैं। ऐसी भी चर्चा सामने आई कि जयंत चौधरी ने पांच से सात लोकसभा सीटों की मांग रखी थी लेकिन भाजपा की ओर से चार सीटों का ही वादा किया गया है। भाजपा को पता है कि यदि जयंत को ज्यादा सीटें दी गयीं तो उत्तर प्रदेश की अन्य सहयोगी पार्टियां अपना दल, सुभासपा और निषाद पार्टी भी ज्यादा सीटें मांगेंगी। बताया जा रहा है कि गठबंधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में भी एक पद मिल सकता है।

इस तरह की भी चर्चा है कि जयंत चौधरी की पार्टी 12 फरवरी से पहले भाजपा के साथ आ सकती है और जब 12 फरवरी को भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुजफ्फरनगर पहुँचेंगे तो जयंत चौधरी भी साथ होंगे। हम आपको बता दें कि नड्डा लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर से पार्टी के एक महीने के ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता मोदी सरकार के जन–कल्याणकारी कदमों को रेखांकित करने के अलावा चुनाव घोषणापत्र के लिए किसानों और मजदूरों सहित ग्रामीण आबादी से सुझाव मांगेंगे। पार्टी के सदस्य लोगों से संवाद के दौरान गांवों में गायों और कृषि उपकरणों की पूजा भी करेंगे। देखा जाये तो नड्डा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मुजफ्फरनगर का चयन कर बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है क्योंकि यह क्षेत्र मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध का केंद्र था। हालांकि बाद में केंद्र ने उन कानूनों को वापस ले लिया था लेकिन आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई है।

बहरहाल, जहां तक इंडी गठबंधन की बात है तो बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके कुछ और घटक या उन घटकों के बड़े नेता सत्तारुढ़ एनडीए का दामन थाम सकते हैं क्योंकि देश के राजनीतिक मिजाज से सभी वाकिफ हैं। सभी इस बात को समझ रहे हैं कि देश की ताजा राजनीतिक स्थिति यही है कि दस साल के शासन के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होने की बजाय देश–विदेश में और बढ़ी ही है।

उनका है तो परिवारवाद इनका है तो समाजवाद ?

–निर्मल रानी–

गत दिनों राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो कम गिनाईं परन्तु विपक्ष पर अधिक हमलावर रहे। उन्होंने एक बार फिर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू,इंदिरा गांधी व राहुल गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी पर परिवारवादी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कि "देश ने जितना परिवारवाद का खमियाजा उठाया है, खुद कांग्रेस ने भी उसका उतना ही खमियाजा उठाया है। सदन में ही जब कांग्रेस की ओर से 'बीजेपी में फलते फूलते परिवारवाद' पर सवाल किया गया तो मोदी ने कहा कि उनके लिए परिवारवाद का मतलब एक ही परिवार के कई लोगों के राजनीति में आने से नहीं है। उन्होंने कहा, "अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर व जनसमर्थन से एक से अधिक लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं, जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है।" यानी प्रधानमंत्री ने नेहरू–गांधी परिवार पर हमला बोलने की सुविधाजनक परिभाषा गढ़ डाली। अमितशाह व राजनाथ सिंह का नाम लेकर उन्हें सदन में इसलिये सफाई देनी पड़ी क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कई विपक्षी नेता अक्सर यह सवाल करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह बीसीसीआई के सचिव से लेकर एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष तक किस आधार पर बन जाते हैं ? विपक्ष पूछता है कि जय शाह के पास अमित शाह का पुत्र होने के अतिरिक्त ऐसी कौन सी योग्यता है जिसके आधार पर उन्हें इतने महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त,मनोनीत या निर्वाचित कराया जाता है? इसी तरह राजनाथ सिंह के एक पुत्र जहाँ भाजपा से विधायक हैं वहीं दूसरे भी किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं।

मोदी ने परिवारवाद की नई परिभाषा गढते हुये अपनी ही पार्टी के अनुराग ठाकुर,पियूष गोयल,धर्मेंद्र प्रधान,वसुंधरा व ज्योतिरादित्य सिंधिया,देवेंद्र फड़नवीस,जतिन प्रसाद,आर पी एन सिंह,राव इंदरजीत सिंह व किरण रिजिजू जैसे उन अनेक नेताओं का बचाओ किया जो अपनी पैतृक राजनीति के ही प्रतीक हैं। परन्तु प्रधानमंत्री के अनुसार जो पार्टी,एक परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जिस पार्टी के सारे निर्णय एक ही परिवार के लोग करते हैं, ऐसे दलों व नेताओं के परिवारवाद का देश ने खमियाजा उठाया है?फिर तो प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिये कि 2014 तक भाजपा का जिस बल ठाकरे व उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में 25 वर्षों तक गठबंधन रहा और महाराष्ट्र में अनेक लोकसभा व विधानसभा चुनाव भाजपा –शिवसेना मिलकर लड़ी वह परिवारवादियों से समझौता था या नहीं ? इसी तरह जो शिरोमणि अकाली दल, बादल परिवार की पार्टी है और किसान आंदोलन से पूर्व दशकों तक भाजपा की सहयोगी रही है उसका परिवारवाद प्रधानमंत्री की परिभाषा से कैसे अलग है ? इसी तरह भाजपा जब चाहे तब हरियाणा में एक ही परिवार की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से समझौता कर सकती है ? आज भी भाजपा हरियाणा में जिस जननायक जनता पार्टी (जे जे पी) के साथ सत्ता की साझेदार है वह भी एक ही परिवार की पार्टी है। इसी तरह भाजपा जब चाहे कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पारिवारिक पार्टी पी डी पी से समझौता कर सकती है? बिहार में राम विलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी क्या परिवारवाद की पार्टी का प्रतीक नहीं? कर्नाटक में भाजपा परिवारवादी राजनीति करने वाले येदियुरप्पा के हाथों में क्यों खेलती है? इसी तरह के और भी कई श्परिवारवादीश दल हैं जिनसे भाजपा गठबंधन करने में परहेज नहीं करती। सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि –श्परिवारवाद का देश ने खमियाजा उठाया हैश फिर आखिर उन्हीं की परिभाषा वाले श्परिवारवादियों श से भाजपा के गलबहियां करने का अर्थ व औचित्य क्या ?

दरअसल मोदी सहित भाजपा नेताओं को कांग्रेस व कांग्रेस सहयोगी दलों में ही सारा परिवारवाद नजर आता है। इन्हें केवल राहुल गाँधी,अखिलेश यादव,तेजस्वी यादव जैसे नेता ही परिवारवादी राजनीति के प्रतीक नजर आते हैं। इन्हें राहुल गाँधी की परिवारक कुंडली तो नजर आती है परन्तु उनका कन्याकुमारी से कश्मीर व मणिपुर से मुंबई तक की साहस भरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा नजर नहीं आती ? इन्हें राहुल के पिता व दादी की कुरबानी दिखाई नहीं देती ? इन्हें राहुल की मां सोनिया गाँधी द्वारा प्रधानमंत्री जैसे उस पद का त्याग नजर नहीं आता जिससे आजीवन चिपके रहने के लिये कौन कौन से हथकंडे नहीं अपनाये जा रहे ? लालू यादव व मुलायम सिंह यादव की सामाजिक न्याय की वजह से भी भाजपा इनकी पार्टी की वैचारिक विरोधी है जिसके चलते इनपर परिवारवाद का आरोप लगाती है। पिछले दिनों अपने जिस राजनैतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को 'भारत रत्न' देकर उनसे प्रधानमंत्री पद हड़पने का पश्चाताप किया गया उन्हीं आडवाणी को 22 अक्टूबर 1990 को लालू यादव ने बिहार का मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार किया था। यह घटनाएं भाजपा आखिर कैसे भूल सकती है ? इसी तरह मुलायम सिंह यादव द्वारा अक्टूबर 1990 को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते अयोध्या में कर्फ्यू लगाया गया। उन्होंने बाबरी मस्जिद के आसपास के इलाकों में बैरकेडिंग कर कहा था कि, बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और 30 अक्टूबर 1990 को जब भीड़ ने कारसेवकों के साथ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ना शुरू किया उस समय ढांचे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कारसेवकों पर गोलियां दागी गयी थीं जिसमें कई कारसेवक व साधुओं की जानें भी गयी थीं। बाद में यही आंदोलन जब और उग्र हुआ तो 6 दिसंबर 1992 की घटना के रूप में इसकी परिणति हुई। जाहिर है कांग्रेस,समाजवादी पार्टी व आर जे डी की यही धर्मनिरपेक्ष राजनीति जब रास नहीं आती तो वैचारिक कुंठा से ग्रस्त लोग इनपर परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाकर इन्हें बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं साथ ही जनसरोकार से जुड़े वास्तविक मुद्दों की तरफ से जनता का ध्यान भी भटकाते हैं। यानी इन्हें उनका परिवारवाद तो परिवारवाद दिखाई देता है परन्तु अपना परिवारवाद, समाजवाद नजर आता है ?**

उत्तराखण्ड में समान आचार संहिता

–ललित गर्ग–

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान आचार संहिता (यूसीसी) के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी और इसे विधानसभा में पेश भी कर दिया। अब चार दिनों के विशेष सत्र में इसे आसानी से पारित भी कर दिया जायेगा। इस तरह देश को आजादी मिलने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। इससे पहले गोवा में यह लागू है। आजादी के अमृतकाल में समानता की स्थापना के लिये इससे अपूर्व वातावरण निर्मित होगा। यह उत्तराखण्ड ही नहीं, समूचे भारत की बड़ी जरूरत है। समानता एक सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक लोकतांत्रिक मूल्य है। इस मूल्य की प्रतिष्ठापना के लिये समान कानून की अपेक्षा है। यूसीसी देश की राजनीति के सबसे विवादित मुद्दों में रहा है। हालांकि संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों के रूप में इसका उल्लेख है। इस लिहाज से राजनीति की सभी धाराएं इस बात पर एकमत रही हैं कि देश में सभी पंथों, आस्थाओं से जुड़े लोगों पर एक ही तरह के कानून लागू होने चाहिए। राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति, वर्ग, सम्प्रदाय, जाति जब–तक कानूनी प्रावधानों के भेदभाव को झेलेगा, तब तक राष्ट्रीय एकता, एक राष्ट्र की चेतना जागरण का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। उत्तराखण्ड एवं गोवा के बाद असम और गुजरात जैसे राज्य भी समान आचार संहिता को लागू करने की तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं नरेन्द्र मोदी सरकार यूसीसी लागू करने की मांग जोरदार तरीके से करती आ रही है और इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया है। भारतीय न्यायपालिका की तरफ से भी बार–बार इसे लागू करने की जरूरत बताई जा रही है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि देश में इसे लेकर जागरूकता हाल के दिनों में बढ़ी है और इसका श्रेय भाजपा को दिया जाना चाहिए।

समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत देश के सभी धर्मों, पंथों और समुदायों के लोगों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। भारत के विधि आयोग ने राजनीतिक रूप से अतिसंवेदनशील इस मुद्दे पर देश के तमाम धार्मिक संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए थे। यूसीसी में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, उत्तराधिकार, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एकसमान कानून बनाया जाना है। पिछले कुछ समय से इस पर अच्छी खासी बहस चली है। लिहाजा एक–एक करके अलग–अलग राज्यों में इसे लागू करने और वहां के अनुभव के आधार पर आगे बढ़ने का ख्याल गलत नहीं कहा जा सकता। उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तराखण्ड विधानसभा में इसे पेश किए जाने और वहां बहस शुरू होने के बाद इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर रोशनी पड़ेगी और सभी दुविधाएं, शंकाएं एवं संदेह दूर हो जाएंगे। जो अन्य राज्यों के लिये लागू करने का आधार बनेगी।

भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक धर्म–निरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्मों व संप्रदायों (जैसे– हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, आदि) को मानने वालों को अपने–अपने धर्म से सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार है। भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956 जो कि हिंदू, सिख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा, मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात की जा रही है, जो प्रासंगिक होने के साथ नये बन रहे भारत की अपेक्षा है। अभी मीडिया में छन–छन कर जो सूचनाएं आ रही हैं, उनके मुताबिक शादी, तलाक, अडॉप्शन से जुड़े कानूनों में एकरूपता के जो प्रावधान हैं, वे यूसीसी की मूल अवधारणा के अनुरूप ही हैं। बहरहाल, उत्तराखण्ड राज्य सरकार की यह एक बड़ी पहल है और इस पर अमल की प्रक्रिया ही नहीं, इसके नतीजों पर भी पूरे देश की नजरें रहेंगी।

आज जबकि भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, जी–20 देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत कर चुका है, भारत की अहिंसा एवं योग को दुनिया ने स्वीकारा है, विश्व योग दिवस एवं विश्व अहिंसा दिवस जैसे आयोजनों की संरचना हुई है। इन सब सकारात्मक स्थितियों को देखते हुए भारत की कानून विषयक विसंगतियों को दूर करना अपेक्षित है।

तस्करों के जमानतदारों पर कसेगा शिकंजा, पुलिस खंगाल रही कुंडली

संवाददाता–कुशीनगर। पशु और शराब तस्करों के जमानतदारों पर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में जुटी है। दो साल के अंदर दबोचे गए पशु और शराब तस्करों के अधिकतर जमानतदार जिले के ही लोग हैं। ऐसे लोगों की कुंडली पुलिस खंगाल रही है। इससे पुलिस तस्करों का जिले में फैले नेटवर्क को तोड़ने में कामयाब हो सकती है। अब तक तस्करों की जमानत लेने वाले करीब 30 लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस की शिकंजा कसने के बावजूद कुशीनगर जिले के रास्ते बिहार में पशु और शराब की तस्करी नहीं रुक रही है। पुलिस मुठभेड़ में 50 से अधिक तस्कर पकड़े जा चुके हैं। बावजूद, तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही है। कार्रवाई के बाद जिन आरोपियों को पुलिस जेल भिजवाती है। उनकी जेल से रिहाई कराने वाले में अधिकतर जमानतदार जिले के ही रहने वाले है। पुलिस ने गोमनीय तरीके से करीब 30 जमानतदारों की सूची तैयार कर ली है। पुलिस इनके बारे में पता लगा रही है। सूत्रों की मानें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर, मेरठ समेत कई जिले के रहने वाले पशु तस्करों का कुशीनगर जिले में फैले नेटवर्क के पीछे कीसका हाथ और इसके पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है। गिरफ्तार गए कैरियरों के पास से उनके मोबाइल में कुशीनगर के अलावा,गोरखपुर,गोपालगंज के लोगों का मोबाइल नंबर मिला है। लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस साबूत नहीं मिल रहा है कि वे तस्करों के सरगना तक पहुंचे। इस लिए पुलिस तस्करों का जमानत कराने वालों की कुंडली खंगालना शुरू किया है। पुलिस अपनी योजना में सफल रही तो गैर जिले के तस्करों के कुशीनगर जिले में फैले नेटवर्क का भंडाफोड़ जल्द हो –तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। –धवल जायसवाल, एसपी ने कहा किगोरखपुर जोन का पहला जिला कुशीनगर है, जहां मुठभेड़ में तस्करों व बदमाशों को गोली लगी है। बाहरी तस्करों का जो भी नेटवर्क जिले में फैला है, उसे तोड़ने के लिए तस्करों की जमानत लेने वालों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। तस्करों से तार जुड़ने का साक्ष्य मिलने पर इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

समाज के सर्वांगिण विकास के लिए शिक्षा जरूरी –अरविन्द राजभर

संवाददाता–देवरिया। विकास खंड के कुकुर घाटी में बुधवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव डॉ अरविंद राजभर ने कहा कि शिक्षा से ही किसी भी समाज का विकास संभव है। उन्होने लोगो को अपने बच्चो को शिक्षित करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि अब शौचालय आवास पर नहीं रोजगार पर वोट मिलना चाहिए। रोजगार के लिए बच्चों को आधी रोटी खाकर भी शिक्षित बनाना होगा। राजभर ने पूरे देश में एक समान की शिक्षा व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता पर बोलते हुए कहा कि इससे दलित शोषित और कमजोर लोगों के बच्चे भी पढ़ पाएंगे और शिक्षा में गुणवत्ता आएगी तथा इसका लाभ मिलेगा। अरविंद राजभर ने प्रदेश में दारू बंद करने की मांग करते हुए कहा कि दारू की दुकान बंद होनी चाहिए।

वर्तमान बजट में प्रदेश सरकार ने 2300 करोड़ रुपए की व्यवस्था दारू उत्पादन से की है। उसको बंद कर छोटे.छोटे कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना जरूरी है। प्रदेश प्रवक्ता राघवेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सुभासपा पार्टी गरीबो के हक हकुक व उनकी समस्यायों के लिए लड़ती है। अन्य दल केवल वोंट की रोटी सेकने का काम करते है। हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के नब्ज को सरकार तक पहुंचाया जाए और न्याय दिलाया जाए।

जनसभा को सुनीता राजभर, बृजेश राजभर, विरेन्द्र, राम आशीष आदि ने सम्बोधित किया।

पेयजल परियोजनाओं को देखने पहुंचे डीएम, टोटी खोल जाना हाल, सड़क देख आया गुस्सा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

संवाददाता–गोण्डा। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल उपलब्ध कराए जाने के लिए संचालित 4 पाइप पेयजल परियोजनाओ का डीएम ने जमीनी हकीकत को परखा। उन्होंने गांव में लोगों के घरों पर लगाई गई टोटियों को खोलकर देखा इसके साथ ही पाइपलाइन डालने के लिए को खोदी गई सड़क का ठीक ढंग से मरम्मत न होने पर डीएम नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्यवाई की जाएगी।

जिले के उतरौला तहसील की ग्राम पंचायत कांदवारी, लकमा, पिपरा एवं जिगना में पाइप पेयजल परियोजना का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत कांदवारी में एलएनटी ने सौर ऊर्जा पाइप पेयजल परियोजना का कार्य किया जा रहा है। ओवरहेड टैंक के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बोरिंग एवं अन्य कंपोनेंट के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। इस दौरान डीएम ने ग्राम में योजना से लाभान्वित ग्रामीणों से वार्ता किया गया। डीएम से स्वयं नल की टोटी खोलकर पानी आ रहा है कि नहीं इसको देखा। उन्होंने घरों पर दिए गए नल का फाउंडेशन बनाए जाने एवं टोटियों को अच्छी तरह से फिट किए जाने का निर्देश दिया। पाइप लाइन बिछाने के दौरान को खोदी गई। सड़कों के मरम्मत के कार्य पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से सड़क का लेवल मेंटेन करते हुए मरम्मत कार्य किए जाने का निर्देश दिया। सड़क के रेस्टोरेशन का कार्य ठीक ढंग से नहीं किया गया तो जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने का कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। पाइप पेयजल परियोजना के तहत दिए जा रहे कनेक्शन में अंतिम घर तक जल पूरे प्रेशर के साथ पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए। सप्लाई किया जा रहे जल की जांच गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी से कराया जाए। प्रत्येक दशा में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ग्राम पंचायत लकमा में सौर चलित ओवरहेड टैंक के निरीक्षण के दौरान डीएम द्वारा गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य किए जाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने का कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से किए जाने एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। ग्राम पंचायत जिगना में पाइप लाइन बिछाने एवं घरों में नल कनेक्शन के कार्य का जायजा लिया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी व अन्य संबंधित अधिकारीकर्मचारीगण उपस्थित रहे।

विद्यालय में छात्र–छात्राओं की उपस्थिति कम पाये जाने पर डीएम ने जताई नाराजगी

संवाददाता–श्रावस्ती। जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने विकास खण्ड गिलौला के उच्च प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर खुरहरी का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान नामांकन के सापेक्ष छात्र–छात्राओं की उपस्थिति कम पाए जाने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही उपस्थिति में सुधार न होने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने मध्यान्ह भोजन की जानकारी ली। इस पर बताया गया कि मीनू के अनुसार मध्यान्ह भोजन में तहरी बनी थी। जिसमें सोयाबीन न पाये जाने पर प्रधानाध्यापक को फटकार लगाते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही विद्यालय परिसर में किचन, पेयजल, साफ–सफाई, शौचालय आदि व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि अध्यापन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जायेगी। सभी शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने दायित्वों को बखूबी निर्वहन करें और नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शिक्षित कर भाग्य संवारें। जिलाधिकारी ने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को विद्यालय प्रतिदिन भेजें, ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल बन सके।

किशोरी से रेप मामले में एक को दस वर्ष का सश्रम कारावास

संवाददाता–बहराइच। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के जज वरुण मोहित निगम ने एक किशोरी के साथ रेप मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त पर पचास हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न करने पर दोषसिद्ध अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

एडीजीसी क्रिमिनल सुरेन्द्र मौर्या ने बताया कि नानपारा कोतवाली के एक गांव निवासिनी 16 वर्षीय बेटी 14 मार्च 2015 को गांव के बाहर खेत में शौच को गई थी। वहां पहले से ही घात लगाए बैठे इसी कोतवाली के मथुरा गांव निवासी अयोध्या प्रसाद पुत्र सीताराम ने उसे रेप की नियत से पकड़ा। किशोरी के शोर पर गांव के लोग दौड़े। उन्होंने अयोध्या प्रसाद को पकड़ लिया। इसी दौरान लोक लाज के भय से बेटी ने जहर खा लिया। उसे आनन फानन में अस्पताल मे भर्ती कराया गया। पकड़े गए आरोपी को पुलिस के हवाले करते हुए पीड़ित पिता ने रेप व पाक्सो एक्ट मे अयोध्या प्रसाद को नामजद कर केस दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकोलीगल व कोर्ट में बयान कराए।

इस मामले में विवेचक ने तहकीकात कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिस पर कोर्ट में विचारण शुरू हुआ। कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज हुए। इस मामले में बुधवार को जज ने बचाव पक्ष व अभियोजन स एडीजीसी सुरेन्द्र कुमार मौर्या के तर्कों को सुना। जज ने अयोध्या प्रसाद को दोषसिद्ध पाए जाने पर दस वर्ष का सश्रम कारावास व पचास हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश सुनाया है।

महाविद्यालय बनकर तैयार शिक्षकों की तैनाती का है इंतजार

संवाददाता–श्रावस्ती। बच्चों की शिक्षा बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से अनेक शिक्षण संस्थानों का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन समय से चालू न होने के कारण बच्चों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। विकास क्षेत्र जमुनहा के हरदत्तनगर गिरंट में बनाया गया राजकीय महाविद्यालय बन कर तैयार खड़ा है। लेकिन चालू नहीं हो सका है। विकास क्षेत्र जमुनहा की ग्राम पंचायत हरदत्तनगर गिरंट में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कराया गया है। करीब एक साल पहले महाविद्यालय का भवन बन कर तैयार हो गया है। लेकिन अब तक चालू नहीं हो सका है। महाविद्यालय चालू हो जाने से जिले के 500 से अधिक छात्रों का एक शैक्षिक सत्र में दाखिला हो सकेगा। इससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। जमुनहा क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधा न होने से इंटर मीडियट की शिक्षा के बाद छात्रों को अन्य जनपदों को जाना पड़ता है। जबकि अधिकांश बालिकाओं की पढ़ाई इसलिए बाधित हो जाती है कि नजदीक महाविद्यालय नहीं है। राजकीय महाविद्यालय चालू हो जाने से बालिकाओं को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। कारण है कि जमुनहा क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं है।

वार्षिकोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम

संवाददाता–बलरामपुर। बद्रीनारायन मिश्रा किसान इंटर कॉलेज लैबुड़वा फौजदार पुरवा में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूली बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। विगत कई वर्षो भांति इस साल भी बद्रीनारायन मिश्रा किसान इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य प्रबंधक रामजी मिश्रा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्षा आरती तिवारी, विशिष्ट अतिथि विनय कुमार मिश्रा, गुलाबचंद पाठक, डा. शुभम तिवारी व अनिल तिवारी रहे।

विद्यालय में वार्षिकोत्सव के दौरान छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। प्रबंधक रामजी मिश्रा ने कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को एक नया रुप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित एवं संस्कारित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवारों के बढ़ने के साथ–साथ उनकी युवा पीढ़ी को संस्कारित एवं सकारात्मक मार्ग दर्शन की आवश्यकता है। कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारना आसान होता है। यहां के शिक्षक अपने गुणों से छात्रों को आगे ले जाने के लिए खेल कूद एवं अन्य शिक्षण कार्यो में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिसमें देश–भक्ति गीत फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी, बेटी हिन्दुस्तान की, जीना है तो पापा शराब मत पीना, नाटक, भक्ति गीत आदि की प्रस्तुत की तो एक अलग ही उत्साह नजर आया। इसी वीच छात्राओं ने कई महिलाओं से संबंधित नाटक का भी आयोजन किया। इस दौरान प्रधानाचार्य राजेश मिश्रा ने छात्र–छात्राओ के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आर्शीवाद दिया। इस अवसर पर अध्यापक कर्तारम यादव, मनोज कुमार शुक्ल, सुखदेव तिवारी आदि छात्र–छात्राएं मौजूद रहे।

वयोश्री योजना में चयनित यूपी के 12 जिलों में गोंडा भी शामिल

संवाददाता–गोंडा। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना जिले के बुजुर्गों के बुढ़ापे की लाठी बनेगी। योजना के तहत चयनित यूपी के 12 जिलों में गोंडा भी शामिल है। इसके तहत जरूरतमंदों बुजुर्गों को सहायक उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर की ओर से जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है। डीएम नेहा शर्मा के निर्देश पर जिले में सर्वे करके जरूरतमंद बुजुर्गों को तलाशने का काम तेजी से किया जा रहा है। अभी तक जिले में 1048 पात्रों को योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इन लोगों को जल्द से जल्द योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय वयोश्री योजना संचालित की जारी है। इसमें देश के 59 जिलों को केवल शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को वयोश्री योजना में शामिल किया गया है। इनमें गोंडा के अलावा वाराणसी, हमीरपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर ,श्रावस्ती, मिर्जापुर, जालौन ,चंदौली, उन्नाव, मैनपुरी और महोबा जिला शामिल है। जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले में पात्रों को चिह्नित करके सूचीबद्ध किया गया है। उनका सर्वे तकरीबन 2 महीने पहले आई टीम ने कर लिया था और सूची बनाकर प्रदेश स्तर पर भेज दिया था। योजना के तहत जरूरतमंदों को जरूरी उपकरण भी मुहैया कराए जाएंगे। जिसके लिए चिह्नित स्थानों पर कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। ऐसे लोगों की पहले ही सूची तैयार कर ली गई है । जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारीका नाम और मोबाइल नंबर सर्व प्रथम मांगा गया था जिसको भेज दिया गया है और पूरी जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई है। जहां–जहां पर सहयोग मांगा जा रहा है विभाग की ओर से वहां पर सहयोग किया जा रहा है।

युवाओं को जोड़ संगठन को और मजबूत करें युवा कांग्रेसी –गोविंद

संवाददाता–देवरिया। किसी भी संगठन या समाज को मजबूत करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव गांव जाकर युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने का काम करें। उक्त बातें बुधवार को युवा कांग्रेस की बैठक को सम्बोधित करते हुए युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गोविंद मिश्र ने कही। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार की युवा विरोधी नीतियों के कारण नौजवान परेशान हैं। युवा कांग्रेस के जिला मीडिया कोआर्डिनेटर सत्यम पांडेय ने कहा कि सरकार का दो करोड़ लोगों को नौकरीदेने का वादा केवल कागजी बन कर रह गया है। क्षेत्र की अधिकांश सड़कें जर्जर हो गई है।अब बिना कांग्रेस की सरकार बने आमजन का भला नही हो सकता है। बैठक के दौरान बरहज के बारा दीक्षित निवासी अभिषेक दीक्षित को युवा कांग्रेस आउट रिच सेल का जिला चेयरमैन बनने पर बधाई दी गई। बैठक को धर्मवीर ,भारती,विराट यादव,अखिलेश मिश्र,हर्षित सिंह, सन्नी पांडेय, किशन कुमार,सैयद फिरोज अहमद, रीना भारती, सिकन्दर, रोहित यादव, राहुल मिश्र, मोहित कुमार, प्रियेश पांडेय, जाबिर खान, रमेश मद्देशिया आदि ने सम्बोधित किया।

मेहनत से होने वाला काम सफलता देता है

संवाददाता–बलरामपुर। एमएलके पीजी कॉलेज के संस्थापक महाराजा सर पाटेश्वरी प्रसाद सिंह की स्मृति में आयोजित संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन बुधवार को प्रकाशोत्सव पर्व के साथ हुआ।

प्रकाशोत्सव पर्व का शुभारंभ मुख्य अतिथि महाविद्यालय के संस्थापक जयेन्द्र प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि ऐश्वर्य राज सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल आरके मोहन्ता, बीके सिंह व प्रो. जेपी पाण्डेय आदि ने महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। जयेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि जिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस महाविद्यालय की नींव डाली गई थी उसके सतत विकास के लिए हम प्रयत्नशील रहें यही पाटेश्वरी प्रसाद को श्रद्धांजलि होगी। विशिष्ट अतिथि ऐश्वर्य राज सिंह ने कहा कि बलरामपुर राज परिवार अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है। सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल आरके मोहन्ता ने कहा कि महाविद्यालय में पहली बार शिक्षकों के प्रयास से पेटेंट कार्य को बढ़ावा मिला है । संयुक्त सचिव बीके सिंह ने कहा कि यदि मेहनत और लगन से कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। कार्यक्रम का संचालन डा. देवेंद्र कुमार चौहान ने किया। इस दौरान विभिन्न कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावियों को महाराजा जयेन्द्र प्रताप सिंह ने स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र व दस–दस हजार रुपए का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में रोहित कुमार कसौधन, मनीष पाण्डेय, आयुषी गुप्ता, रिफत रियाज, लता पटवा, तुषार अग्रवाल, विनोद कुमार, आयुष शुक्ल, श्वेता भट्ट व उमा मणि शुक्ल शामिल रहे।

कामख्या और काली के नगरी की 'आस्था' पहुंची सरयू तीरे

संवाददाता–गोण्डा। कामख्या और काली की भूमि से चली दो आस्था स्पेशल ट्रेनें बुधवार को अलग–अलग समय पर कटरा शिवदयालगंज स्टेशन पर पहुंचीं। इनमें से एक ट्रेन पश्चिम बंगाल के बर्धमान और दूसरी असम के लीडो से मंगलवार को चली थी। प्लेटफार्म पर अयोध्या की जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह और डीआरएम लखनऊ आदित्य कुमार की अगुआई में रामभक्तों का जोरदार स्वागत किया गया। ट्रेन से उतरने के पश्चात सभी श्रद्धालुओं को ई–बसों से अयोध्या रवाना कर दिया गया। मंगलवार को अयोध्या आए श्रद्धालु बुधवार के अपराह्न उसी ट्रेन से सवार होकर मुंगेर के लिए कूच कर गए। आस्था स्पेशल से आने वाले यात्री बेहद उत्साहित और उर्जावान नजर आए। रेल विभाग के विशेष खिदमतदारी की खुशी के साथ राम मन्दिर के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने का खास उमंग भी इन लोगों में देखने को मिला। बंगभूमि से पहुंचे यात्रियों ने हरे रामा के साथ हरे कृष्णा के जयकारे लगाए। राम के आस्था में सरोबार हुआ कटरा स्टेशनरू अयोध्या के सन्निकट स्थित कटरा शिवदयालगंज रेलवे स्टेशन इन पूरी तरह से श्रीराम की आस्था में सरोबार है। स्टेशन पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों से चौबीसों घंटे श्राम आएगे तो अंगना सजाएगे श की मधुर धुन गुंजायमान हो रही है। यहां तैनात सभी कर्मी बेहद विनम्रता और उत्साह के साथ अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे है। आस्था स्पेशल के आने से पूर्व ही प्लेटफार्म पर सभी पलक पांवड़े बिछाकर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार खड़े नजर आते है।

न ही कोई हड़बड़ी और न ही कोई अफरातफरीरू आस्था स्पेशल ट्रेन के प्लेटफार्म पर पहुंचते ही माइक से श्रद्धालुओं के लिए आराम से बोगी पर उतरने का संदेश प्रसारित होने लगता है। रेलवे की ओर से हर बोगी के लिए एक कैप्टन और एक अटेंडेंट तैनात किया गया है। इनको बोगी से उतरे सभी यात्रियों को सुरक्षित और आरामदेह तरीके से बाहर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। प्लेटफार्म पर लखनऊ से कुली बुलाकर लगेज ढोने के लिए लगाए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई है। वापसी के दौरान ट्रेन से आए सभी यात्रियों की गणना पूरी हो जाने बाद ही ट्रेन को हरी झंडी दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों तक परीक्षार्थियों का सफर होगा आसान

संवाददाता–बलरामपुर। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर शासन काफी गंभीर है। परीक्षार्थियों की समस्या को देखते हुए परीक्षा केन्द्रों तक परिवहन बस संचालन की पहल की गई है। इस पहल से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षा देने जाने वाले परीक्षार्थियों को काफी सहूलियत मिलेगी । जिले में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केन्द्रों पर 35हजार परीक्षार्थी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। बोर्ड परीक्षाएं आगामी 22 फरवरी से शुरू हो हो रही हैं। विभाग की मानें तो करीब 18 केंद्र ऐसे हैं जहां परीक्षार्थियों को 15 से 25 किलोमीटर की दूरी पर बने केंद्र पर परीक्षा देनी है। ऐसे में केंद्र पर समय से पहुंचने के लिए परीक्षार्थियों को बड़ी चुनौती थी। जिसको देखते हुए शासन ने दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष बसों को चलाने की पहल की है। शासन के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने परिवहन विभाग से ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की उपलब्धता को लेकर कवायद शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा महकमा ने बोर्ड परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में बच्चों को केंद्र तक पहुंचाने के लिए मार्ग एवं समय निर्धारित कर बसों का नियमित संचालन शुरू करने की बात कही है।

यूपी बोर्ड परीक्षा में मुख्य विषय में परीक्षा के दौरान बसें रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने की अपील की है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर परीक्षा के दौरान बसों का संचालन प्रत्येक मार्ग पर करने की अपील की है। विशेष तौर पर गणित, हिंदी, अंग्रेजी व विज्ञान समेत अन्य प्रमुख विषयों की होने वाली परीक्षाओं के दौरान छात्राओं की संख्या में वृद्धि की भी आवश्यकता बताई है। सरकारी बसों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज केंद्र पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को काफी राहत मिलेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा आगामी 22 फरवरी से होना निर्धारित है। गोविंद राम, डीआईओएस ने कहा कि शासन के निर्देश पर परिवहन महकमा से ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी बसों को संचालित करने की वार्ता की जा रही है। दूर दराज परीक्षा केंद्रों तक बसों का संचालन हो सके इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग पूरे प्रयास में जुटा है।

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)

न्यायालय–श्रीमान मुख्य राजस्व अधिकारी महोदय अयोध्या

कम्प्यूटर वाद सं.201964230000012/2019

राजेश कुमार सिंह आदि

बनाम

गांवसभा आदि

बनाम–1–वृजनाथ सिंह 2–तारेन्द्र प्रताप सिंह 3– पवन कुमार सिंह पुत्रगण स्वर्गीय जगदीश सिंह 4– क्रान्ति कुमार सिंह पुत्र वीरेन्द्र प्रताप सिंह 5– शान्ती सिंह पत्नी स्वर्गीय वीरेन्द्र प्रताप सिंह 6– सभाजीत सिंह पुत्र नरेन्द्र प्रताप सिंह 7– उर्मिला पत्नी स्वर्गीय नरेन्द्र प्रताप सिंह समस्त निवासीगण ग्राम– बरईखुर्द मजरे रामनगर धौरहरा परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद– अयोध्या

तारीख पेशी 13–02–2024

चूंकि उपरिनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2024 के माह 02 के 13 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 24 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

विजलेंस को मौके से ही आनलाइन करनी होगी रिपोर्ट

संवाददाता–देवरिया। बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस की टीम छापेमारी करती है। इसके बाद भी लाइन लास में कमी नहीं आ पा रही है। वहीं कुछ मामलों में विजिलेंस की छापेमारी पर भी सवाल उठता रहा है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन ने छापेमारी के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराना अनिवार्य कर दिया है। जांच के बाद मौके से ही जांच आख्या निर्धारित प्रारूप में आरएमएस पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा। जिले में लगभग 4.65 लाख विद्युत उपभोक्ता बिजली का उपयोग करते है। इसके लिए जिले में 42 विद्युत 33ध्11 केवी विद्युत उपकेन्द्र से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति किया जाता है। जिले को मिलने वाली बिजली में 20 से 25 प्रतिशत की बिजली लाइन लास में चली जाती है। क्षेत्र के कुछ लोग अवैध रुप से बिजली का उपयोग करते है। इसके खिलाफ विजलेंस छापेमारी करती है। इसे पावर कार्पोरेशन के एमडी पंकज कुमार ने गंभीरता से लेते हुए सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विजिलेंस की टीम छापेमारी करते समय वीडियो रिकार्डिंग और फोटोग्राफी भी करेंगे। इसके साथ ही मौके पर जांच रिपोर्ट को निर्धारित प्रारूप में आरएमएस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। जिससे क्षेत्र में हो रहे बिजली चोरी पर रोक लगाया जा सके। विभाग की प्रतिमाह हो रहे लाखों के नुकसान को कम किया जा सके।

विजिलेंस टीम को मीटर की चेकिंग के समय जियोटैग फोटो इस प्रकार लेना होगा कि मीटर की रीडिंग के साथ ही तिथि व समय भी फोटो में अंकित दिखे। यदि उपभोक्ता चेकिंग टीम के साथ फोटो लेना चाहता है तो उसके साथ फोटो लेना होगा। चेकिंग के बाद मौके पर ही जांच आख्या तय प्रारूप में आरएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। इसके लिए जांच टीम प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

उपभोक्ताओं घर पर गई विजिलेंस की टीम के छापेमारी के दौरान सदस्यों से नाम व मोबाइल नंबर पूछ सकता है। उनके परिचय पत्र को देख सकता है। परिसर में पुरुष के नहीं होने पर परिसर के अंदर जांच कराने से रोक सकता है। महिला कर्मी टीम में होने पर ही परिसर के अंदर जांच की जा सकेगी। जांच में पाई गई कमियों का विवरण उपभोक्ता जान सकता है। बिजली चोरी की स्थिति में मौके पर ही राजस्व निर्धारण करते हुए अनुमानित राशि उपभोक्ता को बतानी होगी। जीसी यादव, अधीक्षण अभियंता ने कहा कि जिले में विभाग की विजिलेंस टीम को छापेमारी के दौरान अपने छापेमारी के दौरान वीडियोग्राफी और फोटो लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही जांच आख्या मौके पर आन लाइन करना होगा। इसके लिए आलाधिकारियों ने निर्देश दिया है।

परीक्षार्थियों का शुरू हुआ प्रवेश–पत्र का वितरण

संवाददाता–बलरामपुर। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा महकमा तैयारी में जुटा हुआ है। इस बार परीक्षार्थियों के साथ कक्ष निरीक्षक पर भी पहरा होगा। बोर्ड परीक्षा में करीब चार हजार शिक्षक कक्ष निरीक्षक की जिम्मेदारी निर्वहन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद से परीक्षार्थियों की ऑनलाइन प्रवेश पत्र निर्गत किए जा गए हैं जिन्हें विद्यालयों की ओर से अपलोड कर वितरित किया जा रहा है। जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 64 केंद्र बनाए गए हैं। इन केन्दों पर करीब 35 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस बार बोर्ड के नए नियम के अनुसार परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षकों को स्कूल के समय परिचय पत्र के साथ आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड दिखाने पर ही उन्हें केंद्र पर प्रवेश मिल सकेगा। यह व्यवस्था नकल विहीन परीक्षा के तहत की गई। इतना ही नहीं परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के पहले कक्ष निरीक्षक एवं केंद्र व्यवस्थापक के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। किसी भी केंद्र पर लापरवाही पाए जाने पर केंद्र व्यवस्थापक एवं कक्ष निरीक्षकों की जिम्मेदारी होगी। इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय गोविंदराम की मानें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार कक्ष निरीक्षक से बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगाई जाएगी। परीक्षा के लिए प्रवेश–पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद से ऑनलाइन अपलोड किए गए हैं। जिन्हें

सराफा व्यापारी का कर्मचारी 11 किलो चांदी लेकर फरार

संवाददाता—गोरखपुर। घंटाघर में स्थित अलंकार ज्वेलर्स का 11 किलो चांदी गायब हो गया। आरोप है कि कर्मचारी आशुतोष वर्मा और उसके पिता ने मिलकर चांदी को गायब किया है। गहने के मिलान पर सच्चाई सामने आने के बाद पीड़ित ने कैंट थाने में तहरीर दी है। पुलिस आरोपी पिता–पुत्र पर केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइंस के हरिओम नगर निवासी नीरज सर्राफ की घंटाघर में अलंकार ज्वेलर्स यूनिट कृष्ण विहारी लाल ज्वेलर्स प्रालि नाम से दुकान है। नीरज ने दी तहरीर में लिखा है कि दुकान पर रोजाना बिक्री के बाद अन्य सोने और चांदी गहनों का मिलान करके उसे लॉकर में रख दिया जाता है। दुकान पर तैनात कर्मचारी आशुतोष वर्मा बीते 10 दिनों से ज्वेलरी में टंच लगाने के बहाने से मिलान करने से इंकार करता रहा। दो फरवरी को गहनों का मिलान करने की बात पर बिना बताए कहीं चला गया। इसके बाद जब गहनों की जांच हुई तो पता लगा कि 11 किलो वजन का चांदी के गहने गायब हैं। जेवर कम होने के बारे में पूछने पर वह टालमटोल करने लगा। बाद में उसने दुकान पर आना बंद कर दिया। उसके पिता ने बेटे की गलती मानते हुए धीरे धीरे सामान या पैसा लौटा देने की बात कही। बाद में आरोपी के पिता भी जानमाल की धमकी देने लगे। तहरीर के आधार पर आशुतोष वर्मा के खिलाफ संपत्ति के विषय में विश्वास का आपराधिक हनन करने और जानमाल की धमकी देने का केस दर्ज करके पुलिस जांच कर रही है।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत
इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
निगरानी सं0 524
अदालत—श्रीमान उप संचालक चकबन्दी बस्ती जिला—बस्ती
माधव प्रसाद
बनाम
राजेन्द्र प्रसाद आदि
1. राजेन्द्र प्रसाद 2. इन्द्रनाथ पुत्रगण रामअजोर 3.जयराजी बेवा राम अजोर 4. मनोज कुमार पुत्र राम आज्ञा 5. जगमाता बेवा रामाज्ञा 6. गेना देवी बेवा ईश्वरदीन 7. शोभावती पत्नी ब्रहमादीन, 8. ब्रहमादीन पुत्र बीदुर निवासीगण मौजा पगार तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला—बस्ती

तारीख पेशी 06—03—2024

अपील बनराजी निर्णय अदालत बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मुकाम बस्ती
मयरिखा 24 महीना 04 सन् 2023 ई0 रेस्पान्डेन्टस

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी माधव प्रसाद ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 06 महीना 03 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 24 माह 01 सन 2024 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत
इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
प्रकीर्ण सिविल अपील सं0 46/2023
वाद सं0 1212/2020
अदालत—श्रीमान जिला जज महोदय बस्ती जिला—बस्ती
शमीम अहमद आदि
बनाम
राम हरीश आदि
1. रामहरीश उम्र 58 साल पुत्र कामता प्रसाद साकिन तेनुआ तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरव तहसील रूधौली जिला—बस्ती पोस्ट मझौवामीर
2. परवेज आलम उम्र 48 साल पुत्र स्व0 निसार अहमद साकिन तुरकहिया तप्पा देवरांव परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला—बस्ती
विपक्षीगण प्रथम वर्ग
3. वसीम अहमद उम्र 39 साल पुत्र अब्दुल मजीद साकिन मनहनडीह तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला—बस्ती
विपक्षीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 12—03—2024

अपील बनराजी अदालत मुकाम मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्टस

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 12 महीना 03 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत— श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्णवाद सं. 11/2024
रामकमल त्रिपाठी —सायल
1. रामकमल त्रिपाठी उम्र लगभग 58 साल पुत्र स्व0 केशरी प्रसाद त्रिपाठी निवासी मौजा गड़ाकुल पो0 शोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हाल मुकाम ग्राम पड़री तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला—बस्ती

तारीख पेशी 12—03—2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम—1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद
हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती बतारीख पेशी 12—03—2024 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा। अलमरकूम 07 माह 02 सन 2024 ई0।

द0 हाकिम

पत्रकारों की सुरक्षा, बीमा, गुजारा भत्ता जैसे बिन्दुओं पर सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना सराहनीय-अरुणेश

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने नियम 115 के अंतर्गत सदन में पत्रकारों की सुरक्षा, बीमा, गुजारा भत्ता, आवास एवं उन्हें मूलभूत सुविधा प्रदान किए जाने की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। विधान परिषद में आशुतोष सिन्हा द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करने पर समाचार पत्र एवं पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरुणेश कुमार श्रीवास्तव ने संगठन की तरफ से आभार प्रकट किया है।

जिलाध्यक्ष अरुणेश श्रीवास्तव ने उम्मीद जताई है कि पत्रकारों के सुरक्षा एवं हितों के लिए एमएलसी आशुतोष सिन्हा के द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दे पर सरकार द्वारा अवश्य ही ध्यान दिया जाएगा। अरुणेश श्रीवास्तव ने कहा कि सदन सदन में सपा एमएलसी आशुतोष सिंह द्वारा पत्रकारों के सुरक्षा, गुजारा भत्ता, जीवन बीमा, आवास एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना एक सराहनीय कदम है। पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे अनेक बिंदुओं को उठता रहता है जिससे उसके ऊपर जान का खतरा बना रहता है। इसके अलावा अनेक पत्रकारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। इसलिए हमें विश्वास है कि आशुतोष सिन्हा के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करने और कार्यवाही की मांग पर सरकार जरूर विचार करेगी और पत्रकार के हित के लिए फैसला लेगी।

समाजवादी पार्टी से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने 5 फरवरी को विधान परिषद में पत्रकारों के सुरक्षा और उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। आशुतोष सिन्हा ने सदन में कहा कि मैं सरकार का ध्यान पत्रकारों की सुरक्षा एवं उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं पत्रकारों द्वारा सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं रजक तत्वों के विरुद्ध खबरों को उजागर करने में उन्हें निरंतर धमकियां मिलती रहती है और उनके साथ मारपीट एवं अन्य कहीं दुर्घटनाएं भी होती हैं जिसे कई कलमकार अपनी जान गंवा चुके हैं इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत नैनी होती है जिसके कारण उन्हें अपना वरदानों का गुजारा करने में काफी सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा हेतु पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने करना अति आवश्यक है इसके साथ ही उनका 20 लाख तक का कैशलेस इलाज नए पत्रकारों को 10000 एवं 20 वर्ष तक कार्य कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों को 25000 प्रति माह गुजारा भत्ता एक करोड़ तक का जीवन बीमा उन्हें अन्य योजनाओं से लाभान्वित करना एवं आवास विकास व विकास प्राधिकरण के माध्यम से नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर भवन प्लाट उपलब्ध कराया जाना जनित में है अतः जनित हित में इस लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर हम सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करते हैं।

जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा के प्रधान के रूप में ओम प्रकाश आर्य का चयन

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। महर्षि दयानंद 200 वीं जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में स्वामी दयानंद विद्यालय सुरतीहट्टा बस्ती में आयोजित आर्य संगोष्ठी में जिले में वेद प्रचार कार्यक्रमों के विस्तार पर चर्चा हुई और आचार्य सुरेश जोशी वैदिक प्रवक्ता के नेतृत्व में जिला सभा की चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हुई। जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा के प्रधान के रूप में ओम प्रकाश आर्य का चयन किया गया। सत्येन्द्र वर्मा को उपप्रधान और हरिहर मुनि को मंत्री पद का दायित्व सौंपा गया। शिक्षक मनीष मेंहदीरत्ता को कोषाध्यक्ष, पत्रकार एसोशिएशन संघ बस्ती के अध्यक्ष विनोद उपाध्याय को प्रचार मंत्री कौशल किशोर, अजय अग्निहोत्री, जमुना प्रसाद पांडेय, गरुड़ ध्वज पांडेय, प्रेमचंद त्रिपाठी, शिवपूजन आर्य, राधेश्याम, मुरली धर भारती जी एवं वृजकिशोर को अंतरंग सदस्य का पदभार दिया गया। श्री उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी पुस्तकालयाध्यक्ष चयनित किए गये। किरन आर्या मंत्राणी आर्य समाज टांडा के नेतृत्व में उर्मिला आर्य ने आर्य समाज मंदिर बस्ती में व श्रीमती गीता जी ने आर्य समाज ग्राम खम्हरिया में स्त्री आर्य समाज बनाने का संकल्प लिया। चुनाव अधिकारी सुरेश जोशी ने लोगों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए उनके कर्तव्य का उपदेश दिया।

इस अवसर पर जिला सभा के नवनिर्वाचित प्रधान ओम प्रकाश आर्य ने बताया कि जिले में वेद प्रचार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुंवानो और मनोरमा के संगम पर स्थित लालगंज कस्बे में दिनांक 10फरवरी से 12 फरवरी तक पर्यावरण शोधक यज्ञ, भजन और उपदेश का कार्यक्रम आयोजित है। इसके अलावा जिले के समस्त आर्य समाज मंदिरों में दिनांक 12 फरवरी को महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती अत्यंत हर्षोल्लास पूर्वक मनाई जाएगी। इस अवसर पर मुरली धर भारती प्रधान आर्य समाज गांधी नगर, राधेश्याम, उपेन्द्र जी शर्मा, शिक्षक उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी, प्रेमचंद त्रिपाठी आर्य समाज गजाधर पुर, विनोद जी गंगापुर, आचार्य अजय अग्निहोत्री, जमुना प्रसाद पांडेय जी, आर्य समाज महाराज गंज, चंद्रप्रकाश जी आर्य समाज मुंडेरवा, रामप्रसाद जी आर्य समाज मेहदावल, शिवदयाल जी, शिवप्रसाद प्रबंधक सदानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐंठी, गिरजा शंकर प्रधान, आर्य समाज लालगंज, अश्विनी तिवारी, चंद्र मुनि वानप्रस्थी लालगंज, सहित अनेक आर्य नर–नारियों ने प्रतिभाग किया। सहभोज के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री आशिक अली पुत्र श्री मोहर अली, नाजिम की हैसियत से संस्था मस्जिदे नूरे इलाही, ग्राम–बेलवरिया पो0–पिकौरा, तहसील– हरैया जनपद बस्ती के पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क व प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है। प्राप्त अभिलेख के अनुसार सर्व श्री 01. श्री यार मोहम्मद सदर 2. श्री मोहम्मद हुसैन—ना0 सदर 3. आशिक अली—नाजिम 4. श्री यार मो0— ना0 नाजिम 5. श्री सज्जाक अली—खजांची 6. श्री निसार आलम—मेम्बर 7. श्री लाल मोहम्मद—मेम्बर 8. मोहम्मद फारूक अली—मेम्बर 9. मो0 याकूब मेम्बर दर्शाये गये।

अतः यदि किसी व्यक्ति को उक्त संस्था के पंजीकरण पर आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा और गुण–दोष के आधार पर संस्था के पंजीकरण सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।

विदित हो कि उक्त नोटिस सो0रजि0एक्ट 1860 की धारा 3(1) के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से
(बी0के0 सिंह)
सहायक रजिस्ट्रार
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।

निर्दल पार्षद सौरभ विश्वकर्मा,सपा के विश्वजीत त्रिपाठी समेत 12 अन्य पार्षदों ने थामा भाजपा का दामन

संवाददाता—गोरखपुर। गोरखपुर नगर निगम के 12 पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। लखनऊ स्थिति भाजपा प्रदेश कार्यालय पर दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में इन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में समाजवादी पार्टी के विश्वजीत त्रिपाठी सोनू, निर्दल पार्षद असद गुफरान, अरविंद, रीता, सतीश चंद, सरिता यादव, मीना देवी, छोटेलाल, दिनेश उर्फ शालू, जयंत कुमार, बबलू गुप्ता उर्फ छट्टी लाल, भोला निषाद, माया देवी, समीना (बसपा) सौरभ विश्वकर्मा शामिल रहे। इसमें विश्वजीत त्रिपाठी सपा से कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। अब कार्यकारिणी में भाजपा के दस पार्षद हो जायेंगे। ऐसे में अब भाजपा के 56 पार्षद नगर निगम में हो गए। विश्वजीत त्रिपाठी ने फोन पर ही अपनी और अन्य सदस्यता की पुष्टि की। कहा, डबल इंजन की सरकार में ही देश और प्रदेश का असली विकास संभव है।

एटीएम कार्ड बदलकर जालसाज ने निकाले रुपये

संवाददाता—गोरखपुर। बड़हलगंज क्षेत्र के तिहामुहम्मदपुर निवासी प्रधानाध्यापक पुष्पा राय का एटीएम कार्ड बदलकर जालसाज महिला और पुरुष ने दो दिन में आठ बार में एक लाख आठ हजार पांच सौ रुपये निकाल लिया। पुलिस को तहरीर देकर प्रधानाध्यापक पुष्पा राय ने बताया कि वह तीन फरवरी की दोपहर तीन बजे बड़हलगंज स्टेट बैंक के एटीएम में पैसा निकालने गई थीं। एटीएम केबिन में पासवर्ड डालने पर एरर बताने लगा। उनके पीछे लाइन में एक युवक और महिला खड़ी थी। युवक ने बातचीत करते हुए एटीएम का पिन जान लिया। मदद के बहाने उसने एटीएम कार्ड बदल दिया। रुपये नहीं निकलने पर वह एटीएम से चली गईं। बाद में उनके मोबाइल पर एकाउंट से रुपये का ट्रांजेक्शन करने का मैसेज आया। तब उनको जानकारी हुई।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान प्रथम अपर सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0 176/2019
रामकेवल आदि
बनाम
भारत आदि

1. भारत उम्र लगभग 65 वर्ष पुत्र जंगबहादुर 2. आज्ञाराम उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र रामभुवाल 3. राम सजीवन उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र टीहुल 4. सुदामा उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र छोटकान 5. शिवशंकर उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र राधेश्याम 6. रामनवल उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र बदल समस्त निवासीगण मौजा हसनी तप्पा बांसखोर परगना बस्ती पूरव तहसील रूधौली जिला—बस्ती

तारीख पेशी 01—03—2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 01 माह 03 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा। बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
न्यायालय—श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ई0सी0एक्ट बस्ती
अपील सं0 03/2021
सुधरू
बनाम
हैदर अली

1/2 अब्बास अली 1/3 महबूब अली 1/4 मारूफ अली पुत्रगण हैदरी अली 1/8 जामिना पुत्री हैदर अली 1/10 साजिदा नावालिगान पुत्री हैदर अली श्रीमती साबिरा खातून माता हकीकी साकिनान मौजा गुलरिहवा तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला—बस्ती

तारीख पेशी 14—03—2024

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2024 के माह 03 के 14 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रुप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत–कुसम्हा विकास खण्ड–बस्ती सदर, जनपद–बस्ती

अल्पकालीन निविदा सूचना

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के फेस–2/ के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन योजना के अन्तर्गत ई–रिक्शा क्रय, डस्टबिन क्रय, प्लास्टिक बैंक, एन्सीलेटरी भस्मक क्रय, आर0आर0सी0 सेन्टर हेतु आवश्यक सामग्री तथा सीमेन्ट, बालू, मिट्टी, सरिया, बजरफुट रेता, पाइप, ईट बजारी आदि का कार्य एस0वी0एम0/15 वें वित्त की धनराशि से प्रस्तावित है।

क्र0 सं0	कार्य का प्रकार	सामग्री की अनु0 लागत (लाख में)	प्रतिशत धरोहर राशि	सामग्री की मात्रा	निविदा मूल्य	कार्य की अवधि
1	ई–रिक्शा क्रय	1.75	2 प्रतिशत	2	250	15 दिन
2	कचरा पात्र	5,00,00	2 प्रतिशत	100	250	15 दिन
3	प्लास्टिक बैंक	1,40,000	2 प्रतिशत	40	250	15 दिन
4	आर0आर0सी0 सेन्टर निर्माण	4,25,000	2 प्रतिशत		250	2 माह
5	सामुदायिक इन्सीलेटर	2,00,000	2 प्रतिशत	1	250	15 दिन
6	स्वच्छता किट	4,00,000	2 प्रतिशत	4	250	15 दिन
7	वर्मीकम्पोस्ट	5,00,000	2 प्रतिशत	1	250	15 दिन
8	एस0आर0एस0 सेन्टर	5,00,000	2 प्रतिशत	1	250	2 माह

लगाये जाने हेतु अनुभवी संस्था के चयन हेतु अल्पकालीन सामान्य विक्रेता आमंत्रित की जा रही है। निविदा की शर्ते एवं विवरण निविदा पत्र में अंकित है। जिसे ग्राम पंचायत के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है निविदादाताओं को जी0एस0टी0 फर्म का रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी व निविदा स्वीकृत/ अस्वीकृत का अधिकार निर्माण समिति की होगी। सामग्री घट–बढ़ सकती है। धरोहर राशि 2 प्रतिशत नकद/एफ0डी0आर0 के रूप में ग्राम पंचायत के नाम बन्धक होनी चाहिए निविदा दिनांक 08.02.2024 से 12.02.2024 तक अपरान्ह 2 बजे तक निविदा बाक्स में डाली जा सकती है और निविदा खोलने का समय दिनांक 13.02.2024 को अपरान्ह 3 बजे रहेगा।

ग्राम प्रधान- धिरेन्द्र कुमार वर्मा
ग्राम पंचायत–कुसम्हा
विकास खण्ड–बस्ती सदर
जनपद–बस्ती

सचिव-राजेश कुमार पाण्डेय
ग्राम पंचायत–कुसम्हा
विकास खण्ड–बस्ती सदर
जनपद–बस्ती

पत्रांक–मेमो /निविदा/2023–24 दिनांक 07–02–2024

कार्यालय ग्राम पंचायत–बेलहरा विकास खण्ड–बस्ती सदर, जनपद–बस्ती

अल्पकालीन निविदा सूचना

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के फेस–2/ के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन योजना के अन्तर्गत ई–रिक्शा क्रय, डस्टबिन क्रय, प्लास्टिक बैंक, एन्सीलेटरी भस्मक क्रय, आर0आर0सी0 सेन्टर हेतु आवश्यक सामग्री तथा सीमेन्ट, बालू, मिट्टी, सरिया, बजरफुट रेता, पाइप, ईट बजारी आदि का कार्य एस0वी0एम0/15 वें वित्त की धनराशि से प्रस्तावित है।

क्र0 सं0	कार्य का प्रकार	सामग्री की अनु0 लागत (लाख में)	प्रतिशत धरोहर राशि	सामग्री की मात्रा	निविदा मूल्य	कार्य की अवधि
1	ई–रिक्शा क्रय	1.75	2 प्रतिशत	2	250	15 दिन
2	कचरा पात्र	5,00,00	2 प्रतिशत	100	250	15 दिन
3	प्लास्टिक बैंक	1,40,000	2 प्रतिशत	40	250	15 दिन
4	आर0आर0सी0 सेन्टर निर्माण	4,25,000	2 प्रतिशत		250	2 माह
5	सामुदायिक इन्सीलेटर	2,00,000	2 प्रतिशत	1	250	15 दिन
6	स्वच्छता किट	4,00,000	2 प्रतिशत	4	250	15 दिन
7	वर्मीकम्पोस्ट	5,00,000	2 प्रतिशत	1	250	15 दिन
8	एस0आर0एस0 सेन्टर	5,00,000	2 प्रतिशत	1	250	2 माह

लगाये जाने हेतु अनुभवी संस्था के चयन हेतु अल्पकालीन सामान्य विक्रेता आमंत्रित की जा रही है। निविदा की शर्ते एवं विवरण निविदा पत्र में अंकित है। जिसे ग्राम पंचायत के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है निविदादाताओं को जी0एस0टी0 फर्म का रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी व निविदा स्वीकृत/ अस्वीकृत का अधिकार निर्माण समिति की होगी। सामग्री घट–बढ़ सकती है। धरोहर राशि 2 प्रतिशत नकद/एफ0डी0आर0 के रूप में ग्राम पंचायत के नाम बन्धक होनी चाहिए निविदा दिनांक 08.02.2024 से 13.02.2024 तक अपरान्ह 2 बजे तक निविदा बाक्स में डाली जा सकती है और निविदा खोलने का समय दिनांक 14.02.2024 को अपरान्ह 3 बजे रहेगा।

ग्राम प्रधान–उर्मिला
ग्राम पंचायत–बेलहरा
विकास खण्ड–बस्ती सदर
जनपद–बस्ती

सचिव-राजेश कुमार पाण्डेय
ग्राम पंचायत–बेलहरा
विकास खण्ड–बस्ती सदर
जनपद–बस्ती

पत्रांक–मेमो /निविदा/2023–24 दिनांक 07–02–2024

दैनिक भारतीय बस्ती
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक—दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक—प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय—
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय—
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय—
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेल bhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com